

## G20 और बेहतर वैश्वकि शासन के अवसर

यह एडिटोरियल 03/08/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित **"The trajectory of progress must change"** लेख पर आधारित है। इसमें वैश्वकि शासन प्रणालियों और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिमिस के लिये:

सतत विकास लक्ष्य, G20, G-7, मशिन लाइफ, कोविड-19 महामारी, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, प्रेरणा समझौता

### मेन्स के लिये:

वैश्वकि शासन में स्थानीय शासन की भूमिका एवं महत्व

वशिव जलवायु परविरत्न, सामाजिक-आरथकि असमानता, गरीबी और संघरश जैसे कई संकटों का सामना कर रहा है। आरथकि विकास का वर्तमान मॉडल समतामूलक नहीं है। केवल आरथकि विकास से वशिव की समस्याएँ हल नहीं होंगी; इसे संवहनीय और समतामूलक भी होना चाहयि।

**G20**—जो वैश्वकि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 80% और वैश्वकि आबादी के दो-तहिई का प्रतनिधित्व करता है, वैश्वकि शासन के लिये सबसे प्रभावशाली मंच में से एक है। हालाँकि विरतमान में यह गतरिध का सामना कर रहा है जहाँअमेरिका चाहता है कि इसके सदस्य रूस और चीन को इससे बाहर कर दें, जिन्हें वह अपने व्यक्तिगत लाभ में बाधक के रूप में देखता है। G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत **G-7** के दबाव में नहीं आया है और चाहता है कि G20 मानव जाति के 90% भाग के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करे जो G7 के दायरे से बाहर है।

G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने दुनिया के सभी नागरिकों को एक साथ लाने और दुनिया को सभी के लिये बेहतर बनाने के लियेसुधैर कुटुंबकम’ – एक पृथ्वी, एक परावार, एक भवष्य (One Earth, One Family, One Future) का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भारत ने G20 के लिये LIFE (lifestyles for sustainable development), यानी ‘सतत विकास के लिये जीवन शैली’ का दृष्टिकोण भी प्रस्तावित किया है। इसके लिये “संपूर्ण समाज में सामूहिक कार्यों में नहिति सभी स्तरों पर हतिधारकों के बीच सुसंगत कार्यों” की आवश्यकता है। यह सतत जीवन शैली का समर्थन करने में स्थानीय समुदायों, स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारों और पारंपरकि ज्ञान की भूमिका को भी चहिनति करता है और इसका संवरद्धन करता है।



//

# वैश्वकि शासन को आकार देने में G20 की क्या भूमिका है?

## ■ आरथकि समन्वयः

- आरथकि मुद्रे राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव रखते हैं, इसलिये समन्वयि प्रयासों की आवश्यकता रखते हैं।
- G20 वैश्वकि की प्रमुख अरथवयवस्थाओं के लिये अपनी आरथकि नीतियों पर चर्चा करने और उन्हें संरेखित करने तथावैश्वकि स्थरिता एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- G20 वैश्वकि सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक की और वैश्वकि व्यापार में लगभग 75% की हसिसेदारी रखता है।

## ■ संकट प्रबंधनः

- G20 का उभार वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। तब से इसने तत्काल चुनौतियों का समाधान करने और रकिवरी के लिये रणनीति तैयार करने के लिये वैश्वकि नेताओं को एक मंच पर लाकर संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उल्लेखनीय है कि कोवडि-19 महामारी की प्रतिक्रिया में G20 के नेताओं ने वैश्वकि प्रयासों के समन्वय के लिये एक असाधारण 'वरचुअल लीडर्स समटि' का आयोजन किया था। इस अवसर पर उन्होंने अनुसंधान का समर्थन करने, चकितिसा आपूर्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी करने के लिये प्रतिबिद्धता जाताई।

## ■ वैश्वकि वित्तीय प्रणाली में सुधारः

- G20 वैश्वकि वित्तीय प्रणाली की प्रत्यास्थता और स्थरिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसने भविष्य के संकटों को रोकने के लिये वित्तीय संस्थानों, वनियिमों और नरीक्षण तंत्र में सुधारों पर बल दिया है।
- वित्तीय वनियिम के प्रति G20 की प्रतिबिद्धता के परिणामस्वरूप 'वित्तीय स्थरिता बोर्ड' (Financial Stability Board- FSB) की स्थापना की गई, जो वैश्वकि वित्तीय प्रणाली की नियंत्रणी करता है और उसके बारे में अनुशंसाएँ करता है।

## ■ जलवायु प्रविरतन और सतत् विकासः

- हालाँकि यह इसके प्राथमिक कार्य-दायतिव में शामल नहीं है, लेकिन G20 ने प्रयावरणीय मुद्रों और सतत् विकास को भी संबोधित करने का प्रयास किया है। इस समूह के नियंत्रण संसाधन आवंटन, ऊर्जा नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबिद्धताओं को प्रभावित करते हैं।

## ■ एजेंडों को आकार देना:

- G20 एजेंडे तय कर सकता है और वैश्वकि स्तर पर प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। इसकी चर्चाएँ प्रायः अंतर्राष्ट्रीय आख्यान को आगे बढ़ाती हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का मास्टरप्लान करती हैं।

# वैश्वकि शासन की प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

## ■ विविध उच्चियाँ और प्राथमिकताएँ:

- विभिन्न देशों के विविध और प्रायः परस्पर वरिधी हति और प्राथमिकताएँ हैं। साझा समाधानों की तलाश के क्रम में इन विविध दृष्टिकोणों को संतुलित करना बेहद चुनौतीपूर्ण सदिध हो सकता है।
- प्रेसि समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में जलवायु प्रविरतन प्रतिबिद्धताओं पर असहमतिकी स्थितियिह दरशाती है कविभिन्न देशों के विविध हति साझा समाधानों तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

## ■ समन्वयि कार्रवाई का अभावः

- वैश्वकि शासन के लिये सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नजीकी क्षेत्र सहति विभिन्न हतिधारकों के बीच समन्वयि कार्रवाई की आवश्यकता है।

## ■ असमान संसाधन वितरणः

- वित्तीय और तकनीकी, दोनों तरह के संसाधनों का असमान वितरण वैश्वकि चुनौतियों से नापिटने के मामले में विषमता पैदा करता है।
- विकासशील देशों में प्रायः वैश्वकि शासन पहलों में पूरी तरह से भागीदारी कर सकने और उनसे लाभ उठा सकने के लिये संसाधनों एवं आधारभूत संरचना की कमी पाई जाती है।
  - नमिन आय देशों में कोवडि-19 टीकों की सीमित पहुँच ने समतामूलक वैश्वकि सार्वजनिक कल्याण प्रदान करने में संसाधन विषमताओं और चुनौतियों को उजागर किया।

## ■ वैश्वकि मुद्रों की जटिलता:

- कई वैश्वकि चुनौतियों बहुआयामी प्रकृति रखती हैं जो आरथकि, सामाजिक, प्रयावरणीय और राजनीतिक आयामों तक वसितृत हैं।
- इन मुद्रों के समाधान के लिये व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसे विकसित करना और कार्यान्वयि करना जटिल सदिध हो सकता है।

## ■ शक्ति असंतुलनः

- विभिन्न देशों के बीच शक्ति असंतुलन से वैश्वकि शासन प्रक्रियाओं पर असमान प्रभाव पड़ सकता है।
- शक्तिशाली राष्ट्र नियंत्रण लेने में कम शक्तिशाली देशों की आवाज़ को दरकनार करते हुए असंगत रूप से अधिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) जैसे वैश्वकि नियंत्रण लेने वाले नियमों में असमान प्रतिविवरण से दोषपूर्ण प्राथमिकताओं और समाधानों की स्थितिबन सकती है।

## ■ प्रयावरणीय गरिवट और जलवायु प्रविरतनः

- जलवायु प्रविरतन सहति विभिन्न प्रयावरणीय समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिये वैश्वकि सहयोग की आवश्यकता है। उत्तरदायतिव, शमन रणनीतियों और संसाधन आवंटन पर असहमतियों पर वैश्वकि प्रतिक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है।
- जलवायु वित्त प्रतिबिद्धताओं और उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर साझा सहमतिकी कमी प्रयावरणीय मुद्रों पर वैश्वकि सहयोग प्राप्त करने की कठिनाई को दर्शाती है।

## ■ अल्पावधिविद (Short-Termism) और राजनीतिक दबावः

- संक्षेपित राजनीतिक चक्र (short political cycles) और अलग-अलग देशों के भीतर घरेलू दबावेसे नियन्त्रण लेने की ओर ले जा सकते हैं जो तत्काल लाभ को दीर्घकालिक वैश्वकि लाभों पर प्राथमिकता देते हैं।
- तात्कालिकता या अल्पावधिपर यह फोकस जटिल, क्रमांकित चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- वैश्वकि शासन के मामले में G20 की चुनौतियाँ:
  - G20 की सदस्यता सीमित है जिसमें कई देश और भूभाग शामिल नहीं हैं, जो इसकी वैधता और प्रतिनिधित्व को कमज़ोर कर सकता है।
  - सदस्य देशों, यहाँ तक कि कुछ प्रमुख अरथव्यवस्थाओं के बीच कलह की स्थितिभी वैश्वकि स्तर पर बेहतर समन्वय में बाधा उत्पन्न करती है।

## स्थानीय शासन को सशक्त करना वैश्वकि शासन को कैसे सशक्त कर सकता है?

- SDGs के लिये समुदाय-आधारित समाधान:
  - **सतत विकास लक्षणों (SDGs)** की चुनौतियों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों, जैसे सतत कृषि के लिये स्थानीय कसिनों या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के लिये स्वास्थ्यकरमणों को शामिल करने से संदर्भ-विशिष्ट और अभनिव समाधान प्राप्त हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कसिनों को उनके वातावरण के अनुकूल **जलवायु-कृशल कृषि** अभ्यासों को अपनाने हेतु संलग्न करने से कृषि उत्पादकता और प्रयावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
- स्थानीय सेवाओं और प्रत्यास्थिता को सुदृढ़ करना:
  - शक्ति, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल और समाजिक सुरक्षा जाल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने से प्रत्यक्ष रूप से कल्याण सुनिश्चित होता है और आघातों के प्रति संवेदनशीलता घटती है, जिससे समुदायों के लिये एक सुदृढ़ नीति का नियमान होता है।
    - उदाहरण के लिये, दूरदराज के गाँवों में जल शोधन इकाइयों का नियमान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ाता है और स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य संबंधी SDGs को संबोधित करता है।
- सहभागी शासन और जवाबदेही:
  - स्थानीय नागरिकों, नागरिक संगठनों और नियाचति प्रतिनिधियों को संलग्न करते हुए पारदर्शी नियन्त्रण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करता है कि क्रियान्वित नीतियों समुदाय की आवश्यकताओं, विश्वास-बहाली और जवाबदेही के अनुरूप हों।
- साझा प्रगति के लिये सहकारी नेटवर्क:
  - स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और संसाधन-साझाकरण के लिये मंच स्थापित करने से समुदायों को जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियों का समूहिक रूप से समाधान करने में मदद मिलती है।

## भारत प्रगति के प्रक्षेपवक्त्र को कैसे बदल रहा है?

- भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन को बढ़ावा देता है जो विविधता का सम्मान करता है और राष्ट्रों एवं लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देता है।
- भारत 'LiFE' के दृष्टिकोण की वकालत करता है जो संवहनीय जीवन शैली और उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहित करता है, जो ग्रहीय सीमाओं और मानव गरमियों के अनुकूल है।
  - भारत अन्य देशों को इसके उदाहरण का अनुसरण करने और इसकी सफलताओं एवं असफलताओं से सीखने के लिये प्रेरित करता है।
- इन कदमों के अलावा, भारत सरकार को स्थानीय समुदायों और स्थानीय सरकारों को अपने संसाधनों एवं ज्ञान का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और इन्हें लागू करने के लिये सशक्त बनाना चाहिये।

## G20 वैश्वकि शासन को कैसे सुदृढ़ कर सकता है?

- सहयोगात्मक नेतृत्व और एजेंडा सेटिंग:
  - G20 को सहयोगात्मक नेतृत्व को प्राथमिकता देनी चाहिये, ऐसे एजेंडे स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो इसके सदस्य देशों के विविध हितों को दर्शाते हैं और साथ ही सतत विकास, समान संसाधन वितरण और वैश्वकि स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
    - नियमित संवाद और प्रामर्श यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लिये गए नियन्त्रण समावेशी और समग्र हों।
- संवहनीय अभ्यासों का एकीकरण:
  - G20 को आरथकी नीतियों और नियन्त्रणों में संवहनीयता को एकीकृत करने के लिये सक्रान्ति उपाय करने चाहिये।
    - इसमें **हरति नविश** को प्रोत्साहित करना, **नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण** का समर्थन करना और **चक्रीय अरथव्यवस्था** मॉडल को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
  - सदस्य राष्ट्र समूहिक रूप से **कारबन टट्स्थिता लक्षणों** के लिये प्रतिविद्धता जता सकते हैं और अपनी ऊर्जा नीतियों को प्रेरित समझौते के साथ संरेखित कर सकते हैं।
- संकट का सामना करने हेतु तैयारी को सुदृढ़ बनाना:
  - संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए G20 को वैश्वकि आपात स्थितियों (वित्तीय, स्वास्थ्य-संबंधी या प्रयावरणीय, जो भी हों) पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिये एक रूपरेखा स्थापित करनी चाहिये।
    - इस रूपरेखा में संकटों पर त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये अग्रक्रमीयोजना, सूचना साझेदारी और समन्वय संसाधन आवंटन शामिल किया जा सकता है।
- संसाधन वितरण में अंतराल को दूर करना:

- असमान संसाधन वितरण की समस्या को संबोधित करने के लिये G20 को ऐसी पहल करनी चाहिये जो विकासशील देशों के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझेदारी और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करे।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना में निवेश इन देशों को वैश्वकि शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा संवहनीय समाधानों में योगदान करने के लिये सशक्त कर सकता है।
- स्थानीय शासन को सशक्त करना:
  - G20 को अपने सदस्य देशों को निरिण्य लेने की शक्तियों और संसाधनों को हस्तांतरण करके स्थानीय समुदायों को सशक्त करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - सहभागी शासन के लिये समरथन, स्थानीय सतर पर क्षमता विकास और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिये तंत्रों का निर्माण वैश्वकि चुनौतियों से निपटने में स्थानीय पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

**अभ्यास प्रश्न:** वैश्वकि शासन में स्थानीय शासन के महत्व की चर्चा कीजिये। उदाहरण देकर बताएँ कि स्थानीय शासन वैश्वकि समस्याओं को हल करने में कैसे योगदान कर सकता है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, विगित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न.** नमिनलखिति में से किस समूह के सभी चारों देश G-20 के सदस्य हैं?(2020)

- (a) अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की
- (b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूज़ीलैंड
- (c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वित्तनाम
- (d) इंडोनेशिया, जापान, सिङ्गापुर एवं दक्षिण कोरिया

**उत्तर:** (a)

**प्रश्न.** G-20 के बारे में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये:

1. G-20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय मुददों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी।
2. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा भारत की G-20 प्राथमिकताओं में से एक है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर :** (c)